[2014] 8 एस. सी. आर 32

बैराम मुरलीधर

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1587/2014)

31 जुलाई, 2014

[न्यायाधिपति दीपक मिश्रा और न्यायाधिपति पिनाकी चंद्र घोस]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 321 - अभियोजन से वापसी - लोक अभियोजक का कर्तव्य - एक मामले की जांच कर रहे पुलिस उपनिरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाने वाला मामला दर्ज - राज्य सरकार एक जी.ओ. जारी कर रही है। मामले को वापस लेने के लिए - मामले को वापस लेने के लिए लोक अभियोजक द्वारा धारा 321 के तहत आवेदन– विचारण न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि लोक अभियोजक ने अपने स्वतंत्र दिमाग का उपयोग नहीं किया - उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की - माना: लोक अभियोजक कार्य नहीं कर सकता राज्य सरकार की ओर से डाकघर की तरह - उसे सद्भावना से कार्य करना, अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन करना, खुद को संतुष्ट करना और एक स्वतंत्र राय बनाना आवश्यक है कि मामले को वापस लेने से वास्तव में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित में मदद मिलेगी - इस संबंध में सरकार का एक आदेश लोक अभियोजक पर बाध्यकारी नहीं है- लोक अभियोजक का यह दायित्व है कि वह संक्षेप में बताए कि उसने किस सामग्री पर विचार किया है। वर्तमान मामले में, लोक अभियोजक पूरी तरह से सरकार

के आदेश द्वारा निर्देशित है और मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है - विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी देखा है कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला है - उन्होंने लिया है इस तथ्य पर ध्यान दें कि राज्य सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी थी - यह भी ध्यान देने योग्य है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पाया है कि अभियोजन वापस लेने का कोई औचित्य नहीं था - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले की अपनी गंभीरता है - संबंध में अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक अभियोजक द्वारा दायर आवेदन की प्रकृति के अलावा सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण में गलती नहीं पाई जा सकती है।

धारा 321 - अभियोजन से वापसी - अदालत का कर्तव्य - माना गया: धारा 321 के तहत सहमति देते समय अदालत को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है जिसका प्रयोग यांत्रिक तरीके से नहीं किया जाना है - अदालत केवल पूछने पर ऐसी सहमति नहीं दे सकती है - यह अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करे ताकि यह देखा जा सके कि आवेदन अच्छे विश्वास में और सार्वजनिक हित की सेवा के लिए दायर किया गया है और इस तरह की वापसी न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगी।

अपीलकर्ता, एक पुलिस उप-निरीक्षक और आईपीसी की धारा 366 (ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज मामले में जांच अधिकारी, धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपी के रूप में बिछाए गए जाल के परिणामस्वरूप था। आईपीसी की धारा 366 (ए) (वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता) के तहत मामले में आरोपी के पिता से अवैध परितोषण की मांग करने और स्वीकार करने के आरोपों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) के साथ। उक्त अपहरण कांड में उन्हें न फंसाने तथा आरोप की गंभीरता को कम कर उनके पुत्र के विरुद्ध आरोप पत्र

दाखिल करने का निर्देश दिया. जब मामला आरोप पर सुनवाई के लिए आया, तो लोक अभियोजक ने आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए सीआरपीसी की धारा 321 के तहत एक आवेदन दायर किया, इस आधार पर कि राज्य सरकार ने उसके खिलाफ अभियोजन वापस लेने के लिए दिनांक 23.4.2009 को जी.ओ. जारी किया था। आरोपी अधिकारी के खिलाफ विचारण न्यायालयने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि सरकारी अभियोजक ने जी.ओ. की प्रति के साथ याचिका दायर करने के अलावा अपने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और अदालत के पास आरोपी-अधिकारी के खिलाफ मामले को वापस लेने को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार या परिस्थितियां नहीं थीं। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि लोक अभियोजक ने मामले को वापस लेने के लिए कोई वैध कारण नहीं बताया था, जो संहिता की धारा 321 के तहत वापसी की गारंटी नहीं देता है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. लोक अभियोजक राज्य सरकार की ओर से डाकघर की तरह कार्य नहीं कर सकता। उनसे अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अच्छे विश्वास के साथ अध्ययन करने, खुद को संतुष्ट करने और एक स्वतंत्र राय बनाने की अपेक्षा की जाती है कि मामले को वापस लेने से वास्तव में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित में मदद मिलेगी। सरकारी वकील का यह दायित्व है कि वह संक्षेप में बताए कि उसने किस सामग्री पर विचार किया है। इस संबंध में लोक अभियोजक पर सरकार का आदेश बाध्यकारी नहीं है। वह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने कानूनी दायित्वों से बेखबर नहीं रह सकता। उसे अदालत के प्रति अपने कर्तव्य के साथ-साथ सामूहिक कर्तव्य के प्रति भी अपने कर्तव्य को लगातार याद रखना आवश्यक है। जैसा कि अब्दुल करीम के मामले में माना गया है, अदालत को एक सूचित सहमति देना आवश्यक है। अदालत के लिए खुद को संतुष्ट

करना अनिवार्य है कि सामग्री से यह उचित रूप से माना जा सकता है कि अभियोजन वापस लेने से सार्वजनिक हित की सेवा होगी, सामग्री को तौलना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालाँकि, यह आवश्यक है यह देखना अदालत का काम है कि क्या सहमति देने से कानून का मार्ग बाधित होगा या स्पष्ट अन्याय होगा। संहिता की धारा 321 के तहत सहमति देते समय एक अदालत को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है जिसका प्रयोग यांत्रिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय सिर्फ पूछने पर ऐसी सहमति नहीं दे सकता. अदालत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करे ताकि यह देखा जा सके कि आवेदन अच्छे विश्वास में दायर किया गया है और यह सार्वजनिक हित और न्याय के हित में है। एक अन्य पहलू यह है कि अदालत यह देखने के लिए बाध्य है कि क्या इस तरह की वापसी न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगी। इसमें सावधानीपूर्वक और चिंतित विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ अपराध राज्य और समाज के खिलाफ हैं, क्योंकि सामूहिक न्याय की मांग करता है। जो समाज में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखता है। [पैरा 17-18] [347-एफ-एच; 348-ए-ई]

*अब्दुल करीम आदि आदि बनाम कामताका राज्य और अन्य आदि 2000 (4) पूरक एससीआर 382 = 2000 (8) एस ई सी 710 - पर निर्भर।

1.2. वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने जी ओ एमएस नंबर 268 दिनांक 23 मई, 2009 द्वारा कुछ पहलुओं को गिनाया। लोक अभियोजक ने अभियोजन वापस लेने के लिए अपने आवेदन में जी.ओ. का उल्लेख किया है और अदालत से अनुमति मांगी है। लोक अभियोजक ने जो कहा है वह यह है कि उन्होंने जी.ओ. के रिकॉर्ड पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों का अध्ययन किया है और स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाया है और संतुष्ट हैं कि यह वापसी के लिए उपयुक्त मामला है। लोक अभियोजक द्वारा दायर आवेदन से पता चलेगा कि उसने यांत्रिक रूप से शर्तों-मिसाल के बारे में कहा था। यह

नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में सामग्रियों का अध्ययन किया है और अपना स्वतंत्र दिमाग केवल इसलिए लगाया है क्योंकि उसने ऐसा कहा है। आवेदन में यह बताते हुए सामग्री का अवलोकन करना चाहिए कि उसने कौन सी सामग्री का अध्ययन किया है, संक्षेप में क्या हो सकता है, और क्या अभियोजन को वापस लेने से सार्वजनिक हित में मदद मिलेगी और उसने अपनी स्वतंत्र राय कैसे बनाई है। लोक अभियोजक पूरी तरह से सरकार के आदेश द्वारा निर्देशित है और उसने मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी माना है कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला है। उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि राज्य सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पाया है कि अभियोजन वापस लेने का कोई औचित्य नहीं था। [पैरा 17-18] [347-8, डी-एफ; 348-एफ-एच; 349-ए]

1.3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले की अपनी गंभीरता होती है। मौजूदा मामले में, लोक अभियोजक द्वारा दायर आवेदन की प्रकृति के अलावा अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा भी व्यक्त विचार क्योंकि उच्च न्यायालय को दोष नहीं दिया जा सकता। यह दिखाने का कोई आधार नहीं है कि इस तरह की वापसी से न्याय का उद्देश्य आगे बढ़ेगा और सार्वजनिक हित में मदद मिलेगी। इसके अलावा, लोक अभियोजक की ओर से स्वतंत्र रूप से दिमाग का कोई प्रयोग नहीं किया गया, संभवतः यह सोचकर कि अदालत केवल पूछने पर आदेश पारित कर देगी। नाम दशरथ के मामले में व्यक्त विचार ** वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसमें दो न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी है कि शिव नंदन पासवान के मामले में निर्धारित कानून की विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से सराहना नहीं की गई है। इस न्यायालय ने पाया कि श्योनंदन पासवान के मामले और बाद के फैसलों ने लोक अभियोजक के कर्तव्य और अदालत की भूमिका से संबंधित

सिद्धांतों को निर्धारित किया है और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार बिल्कुल अभेद्य हैं और इसलिए नाम दशरथ में निर्णय तथ्यों पर अलग है। [पैरा 21] [351-सी-जी]

**नाम दशरथ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य आपराधिक अपील संख्या 299/2014 का निर्णय 30.1.2014 को हुआ - प्रतिष्ठित।

शेओ नंदन पासवान बनाम बिहार राज्य और अन्य 1987(1) एससीआर 702 = 1987 (1) एससीसी 288 - अनुसरण किया गया।

बिहार राज्य बनाम राम नरेश पांडे 1957 एससीआर 279 =एआईआर 1957 एससी 389; आर.एम. तिवारी, एडवोकेट बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य 1996 (2) एससीआर 898 = 1996 (2) एससीसी 610; राहुल अग्रवाल बनाम राकेश जैन और अन्य 2005 (1) एससीआर 521 = 2005 (2) एससीसी 377; उड़ीसा राज्य बनाम चंद्रिका महापात्रा 1977(1) एससीआर 335 = 1976 (4) एससीसी 250; निरंजन हेमचंद्र सशित्तल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 (4) एससीआर 767 = 2013 (4) एससीसी 642; डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य 2014 एआईआर 2140 - पर भरोसा किया गया।

बंसी लाल बनाम चंदन लाल 1976 एआईआर 370, बलवंत सिंह बनाम बिहार राज्य (1978) 1 एससीआर 604, सुभाष चंद्र बनाम बैरम राज्य (1980) 2 एससीआर 44; राजेंद्र कुमार जैन बनाम राज्य 1980 (3) एससीआर 982 =एआईआर 1980 एससी 1510 -संदर्भित।

वाद कानून संदर्भ:

आपराधिक अपील संख्या,	विशिष्ट	पैरा 9
299 ऑफ 2014 का निर्णय 30.1.2014 को हुआ		

1987 (1) एससीआर 702	पालन किया	पैरा 9
1976 एआईआर 370	संदर्भित	पैरा 12
(1978) 1 एससीआर 604	संदर्भित	पैरा 12
(1980) 2 एससीआर 44	संदर्भित	पैरा 12
1980 (3) एससीआर 982	निर्भर	पैरा 12
1957 एससीआर 279	निर्भर	पैरा 12
1996 (2) एससीआर 898	निर्भर	पैरा 13
2000 (4) सप्ल एससीआर 382	निर्भर	पैरा 14
2000 (8) एससीजी 710	निर्भर	पैरा 14
2005 (1) एससीआर 521	निर्भर	पैरा 16
1977 (1) एससीआर 335	निर्भर	पैरा 16
2013 (4) एससीआर 767	निर्भर	पैरा 19
2014 एआईआर 2140	निर्भर	पैरा 20

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1587/2014

2010 की आपराधिक याचिका संख्या 1125 में हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 08.12.2011 से।

मधुरिमा तातिया; श्रीधर रेड्डी, वी.एन.रघुपति अपीलकर्ता की ओर से

प्रतिवादी के लिए एटीएम रंगरामानुजम, डी. महेश बाबू, सुचित्रा ह्लांगखॉल, अमजिद मकबूज, अमित के नैन, आदित्य जैन, रामकृष्ण राव, पीवी भास्कर रेड्डी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधिपति दीपक मिश्रा

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में, विशेष अनुमति द्वारा, 2010 की आपराधिक याचिका संख्या 1125 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 8.12.2011 के आदेश की रक्षा पर हमला किया गया है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने सहमति व्यक्त की है। एसपीई और एसीबी मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद द्वारा 2009 के सीआरएल पी नंबर 994 में 2007 के सीसी नंबर 24 में व्यक्त किए गए विचार के साथ, जिसके तहत विद्वान परीक्षण न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "कोड") की धारा 321 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ लंबितमामले को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

3. तथ्यों का खुलासा यह है कि अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू 13 (2) ('अधिनियम' को संक्षिप्त करना) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी के रूप में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार रंगा धर्म गौड़ के बेटे को अपने पड़ोसी की बेटी से प्यार हो गया और वे दोनों 25.01.2006 को भाग गए। पड़ोसी, राधाकृष्ण मूर्ति ने कामारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा- 366 (ए) के तहत आपराधिक मामला संख्या 21/2006 के रूप में दर्ज किया गया था। पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक ने जांच की। और रंगा धर्म गौड़ के बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक हिरासत का सामना करना पड़ा। जब ये सब हुआ तो रंगा धर्म गौड़ जो दुबई में ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, भारत आया और उसे 22.04.2006 को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया और फिर 26.04.2006 को उन तारीखों पर जांच अधिकारी ने रुपये की मांग की। उक्त अपहरण

कांड में उन्हें न फंसाने के लिए 6000/- रुपये का भुगतान किया जाए और साथ ही आरोप की गंभीरता को कम कर उनके बेटे के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाए। जैसा कि रंगा धर्म गौड़ ने राशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की, जांच अधिकारी ने मांग को घटाकर 5000/- रुपये कर दिया। भुगतान करने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए, उन्होंने डीएसपी, एडीबी, निज़ामाबाद रेंज से संपर्क किया, जिन्होंने उचित सत्यापन के बाद सीआरपीसी में मामला दर्ज किया। अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू धारा 13 (2) के तहत 4.5.2006 को क्रमांक 4/एसीबी/एनजेडबी/2006। एफआईआर दर्ज होने के आधार पर जाल बिछाया गया और अंततः आरोपी अधिकारी के खिलाफ सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया।

4. जब मामला आरोप पर सुनवाई के लिए आया तो सरकारी वकील ने 22.06.2009 को आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए इस आधार पर याचिका दायर की कि एपी सरकार ने गृह (एससीए) विभाग की जीपी संख्या 268 जारी की थी। दिनांक 23.05.2009, आरोपी अधिकारी के खिलाफ अभियोजन वापस लेने के लिए। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक की याचिका के साथ संलग्न जी.ओ. एमएस नंबर 268 की प्रति का हवाला दिया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उचित जांच के बाद सरकार ने पाया था कि आरोपी के अच्छे काम को सम्मान दिया जा रहा है। उग्रवाद विरोधी क्षेत्र और अन्य सराहनीय सेवा के लिए उनके मामले को विशेष न्यायाधीश की अदालत में लंबित अभियोजन वापस लेने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जाएगा। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने विभिन्न प्राधिकारियों को संदर्भित किया, लोक अभियोजक की भूमिका और कर्तव्य और संहिता की धारा 321 के तहत न्यायालय की भूमिका के बारे में बताया, और मामले की प्रकृति और राज्य सरकार द्वारा मंजूरी देने पर भी ध्यान दिया। मामले पर मुकदमा चलाने के लिए यह राय दी गई कि सरकारी

वकील ने वास्तव में जी.ओ.एम. की प्रति के साथ याचिका दायर करने के अलावा अपने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था। राज्य सरकार द्वारा जारी; अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन मामले को वापस लेने को स्वीकार करने के लिए न्यायालय के पास पर्याप्त आधार या परिस्थितियाँ नहीं थीं; और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपराध को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आवेदन को अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था, और तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

5. चूंकि विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए अपीलकर्ता ने विद्वान परीक्षण द्वारा बताए गए तथ्यों और कारणों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय और विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान किया। जज ने माना कि विद्वान विचारण जज द्वारा पारित आदेश बिल्कुल त्रुटिहीन था क्योंकि सरकारी वकील ने वास्तव में मामले को वापस लेने के लिए कोई वैध कारण नहीं बताया था और इसके अलावा, तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्राप्त करने में मामले को संहिता की धारा 321के तहत वापस लेने का कोई वारंट नहीं था।

6. हमने याचिकाकर्ता की विद्वान वकील सुश्री मधुरिमा तातिया और राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एटीएम रंगरामानुजम को सुना है।

7. विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या तथ्यात्मक स्कोर प्राप्त करने में न्यायालय द्वारा मामले को वापस लेने के लिए संहिता की धारा 321 के तहत अनुमति देने से इनकार करना उचित था। विवाद को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, सरकारी आदेश का हवाला देना उचित है जिसके तहत मामला वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"2. ऊपर पढ़े गए संदर्भ तीसरे में पुलिस उपनिरीक्षक श्री बैरम मुरलीधर ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है

कि 5.5.2006 को पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, निज़ामाबाद रेंज द्वारा उन पर जाल बिछाया गया था।

निज़ामाबाद, श्री नाम के शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई झूठी और तुच्छ शिकायत पर अपने कर्मचारियों के साथ। कामारेड्डी, निज़ामाबाद जिले के रंगा धर्म गौड़। दरअसल, सीआर संख्या 21/2006 के तहत धारा 366 (ए) भारतीय दंड संहिता के टाउन पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था।

कामारेड्डी ने 01.02.2006 को शिकायतकर्ता के बेटे नरेश गौड़ के खिलाफ। उनके द्वारा 20.03.2006 को ही नरेश गौड़ के खिलाफ न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, कामारेड्डी की अदालत में एक आरोप पत्र भी दायर किया गया था, और इसे पीआरसी नंबर 27/2006 के तहत क्रमांकित किया गया था। इस प्रकार, जैसा कि आरोप लगाया गया है, इस मामले में शिकायतकर्ता या उसके बेटे पर कोई आधिकारिक उपकार नहीं किया जाना था। शिकायतकर्ता ने ही उसे रिश्वत लेने के लिए राजी किया। जब उसने लेने से इनकार कर दिया, तो शिकायतकर्ता ने जबरन उसकी बाईं तरफ की शर्ट की जेब में कुछ नोट डाल दिए। जब उसने अभूतपूर्व कृत्य के लिए शिकायतकर्ता के उक्त कृत्य का विरोध किया, तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके अनुरोधों पर ध्यान दिए बिना उस पर ट्रैप की कार्यवाही की। उन्होंने आगे बताया कि वह अपने वैध कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और उग्रवाद विरोधी कार्य में उनके योगदान के लिए पुलिस उप-निरीक्षक से त्वरित पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार किया गया था। उनकी सेवाओं को 2005 में पुलिस कटिना

सेवा पथकम पुरस्कार देकर मान्यता दी गई थी और वर्ष 2003 के लिए वीरता के लिए प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस पदक के लिए भी उनके नाम की सिफारिश की गई थी। इसलिए अपने पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सरकार से अभियोजन वापस लेने के उनके अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध किया और सेवा में भी बहाल किया जाए।

3. ऊपर पढ़े गए संदर्भ चौथे में, महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद ने आरोपी अधिकारी की दलीलों का खंडन करते हुए कहा है कि आवेदक द्वारा दायर आवेदन में कोई योग्यता नहीं है और यह रखरखाव योग्य नहीं है और ऐसे में सरकार से आरोपी अधिकारी श्री बी मुरलीधर, पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

4. सरकार ने चरमपंथ विरोधी क्षेत्र में उनके अच्छे काम और अन्य सराहनीय सेवा को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तार से जांच की है और आदेश दिया है कि श्री बैरम मुरलीधर, पुलिस उप-निरीक्षक, कामारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन, निज़ामाबाद का मामला। सी.सी. संख्या 24/2007 में अभियोजन को विधिवत वापस लेते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जाए...।"

8. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा दायर वापसी के लिए आवेदन को संदर्भित किया जाना चाहिए। मामले के बारे में तथ्यात्मक मैट्रिक्स बताने के बाद, वापसी की मांग करते समय निम्नलिखित आधार सामने रखे गए:

"यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि मामला इस प्रकार था, सरकार ने मामले की समीक्षा की है और जी.ओ. एमएस नंबर 06 गृह (एससी-ए) विभाग, दिनांक 10.01.2007 को जारी आदेशों को संशोधित करने का निर्णय लिया है और प्रतिवादी/आरोपी अधिकारी को रखा है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकरण के समक्ष अपने बचाव पर और दिनांक 23.5.2009 को जारी जी.ओ. एमएस नंबर 268 गृह (एससी-ए) विभाग, उक्त जी.ओ. विचार के लिए याचिका के साथ दायर किया गया है।

मैं सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि सरकारी आदेश और रिकॉर्ड पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य और स्वतंत्र रूप से दिमाग लगाने पर और सरकार द्वारा दिए गए कारणों से मैं संतुष्ट हूं कि मामला तय सिद्धांतों के अनुसार अभियोजन से हटने के लिए उपयुक्त है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार।

इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों में यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय मुझे प्रतिवादी/अभियुक्त अधिकारी श्री बैरम मुरलीधर के खिलाफ अभियोजन का मामला वापस लेने की अनुमति देने की कृपा करें और इसे वापस लिया हुआ माना जाए और प्रतिवादी/अभियुक्त अधिकारी न्याय और समानता के हित में बर्खास्त किया जा सकता है।"

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इसी तरह के एक मामले में नाम दशरथ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में 2014 की आपराधिक अपील संख्या 299 में 30 जनवरी 2014 को निर्णय लिया गया था कि इस न्यायालय ने संविधान पीठ के पैराग्राफ 69, 70 और 71 को पुन: प्रस्तुत करने के बाद शिव नंदन पासवान बनाम

बिहार राज्य और अन्य में निर्णय ने अभियोजन को रद्द कर दिया और मामले को रिमांड पर ले लिया। उक्त आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:-

> "हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं, ट्रायल कोर्ट के आदेश और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं और सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन वापस लेने की याचिका पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को विचारण न्यायालय में भेज देते हैं। इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में और विशेष रूप से श्योनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य और ऊपर उद्धृत अन्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के प्रमुख निर्णयों के आलोक में।"

10. उक्त मामले में, जैसा कि हमने देखा, उस मामले को वापस लेने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी जहां अधिनियम की धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू धारा 13 (1) (ई) के तहत आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका था और एसपीई और एसीबी के प्रधान विशेष न्यायाधीश ने प्रार्थना स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इस न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी श्योनंदन पासवान के मामले में निर्धारित कानून की सही ढंग से सराहना नहीं की है और तदनुसार आदेश पारित किया है जिसे हमने यहां पहले दोहराया है।

11. हम पहले ही मामले के तथ्यों, सरकारी आदेश और सरकारी वकील द्वारा दायर आवेदन का उल्लेख कर चुके हैं। इससे पहले कि हम विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की कानूनी स्थिरता के संबंध में अपनी राय व्यक्त करें, हम सोचते हैं कि संहिता की धारा 321 के तहत परिकल्पित लोक अभियोजक की भूमिका और न्यायालय के कर्तव्य से संबंधित कुछ अधिकारियों का उल्लेख करना उचित होगा।

श्योनंदन पासवान के मामले में संविधान पीठ ने पुरानी संहिता की धारा 333 का उल्लेख किया और वर्तमान संहिता की धारा 321 के तहत प्रयुक्त भाषा पर ध्यान देते हुए इस प्रकार राय दी: -

> "69. मेरे विचार में, दोनों खंडों को पढ़ते समय एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण कायम रहना चाहिए। धारा 333 उच्च न्यायालय को कोई विवेक या विकल्प नहीं देती है जब इसके तहत कोई प्रस्ताव दिया जाता है। ऐसी स्थिति में धारा 321 भी होनी चाहिए भीतर शक्तियां प्रदान करने के रूप में समझा जाए अभियोजन वापस लेने के लिए लोक अभियोजक को अनुमति देने से इनकार करने के लिए अदालत की सीमित सीमाएँ। यदि इस तरह का सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है तो यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति को जन्म देगा कि जबकि धारा 333 के तहत एक उच्च न्यायालय को असहाय रूप से महाधिवक्ता के प्रतिनिधित्व के आगे झुकना होगा और कार्यवाही रोकनी होगी और अभियुक्तों को आरोपमुक्त करना होगा या बरी करना होगा, अधीनस्थ न्यायालयों को धारा 321 के तहत दायर किए जाने पर सीआरपीसी को अभियोजन वापस लेने के लिए सहमति देने से इंकार करने की शक्ति होगी यदि उसकी राय है कि मामला सबूतों की कमी से ग्रस्त नहीं है। विधायिका का इरादा पुरानी संहिता की धारा 494 और धारा 333 के तहत क्रमशः शक्तियों के प्रयोग में अधीनस्थ न्यायालयों को उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्रदान करने का नहीं होगा। इसलिए प्रदान करते समय इसे बरकरार रखना उचित और उचित होगा धारा 494 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों को अभियोजन चलाने के लिए एक लोक अभियोजक को सहमति देने के लिए विधायिका का इरादा केवल यह था कि अदालतों को पर्यवेक्षी

कार्य करना चाहिए न कि कानूनी अर्थ में न्यायिक कार्य करना चाहिए।

धारा 321 इस प्रकार है:

321. अभियोजन से वापसी.- किसी मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय अदालत की सहमति से, किसी भी व्यक्ति के अभियोजन से आम तौर पर या किसी के संबंध में पीछे हट सकते हैं। एक या अधिक अपराध जिनके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया है; और, ऐसी वापसी पर,-

(ए) यदि यह आरोप तय होने से पहले किया गया है तो आरोपी को ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में आरोपमुक्त कर दिया जाएगा;

(बी) यदि यह आरोप तय होने के बाद बनाया गया है या जब इस संहिता के तहत किसी आरोप की आवश्यकता नहीं है, तो उसे ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में बरी कर दिया जाएगा। (परंतु हटा दिया गया)"

यह धारा मामले के प्रभारी लोक अभियोजक को निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के अभियोजन से हटने में सक्षम बनाती है, लेकिन वापसी के लिए इस आवेदन को अदालत की सहमति प्राप्त करनी होगी और यदि अदालत इस तरह की वापसी के लिए सहमति देती है, यदि कोई आरोप तय नहीं किया गया है तो आरोपी को बरी कर दिया जाएगा या यदि आरोप तय किया गया है या जहां ऐसा कोई आरोप तय करने की आवश्यकता नहीं है, तो बरी कर दिया जाएगा। यह लोक अभियोजक को आरोपी किसी भी

व्यक्ति के अभियोजन से पीछे हटने के लिए तैयार करता है। एक अपराध, दोनों ही मामलों में जब कोई साक्ष्य नहीं लिया गया हो या भले ही संपूर्ण साक्ष्य ले लिया गया हो। इस शक्ति के प्रयोग की बाहरी सीमा "फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय" है।

70. यह धारा उन आधारों के बारे में कोई संकेत नहीं देती है जिन पर लोक अभियोजक आवेदन कर सकता है, या जिन विचारों पर अदालत को अपनी सहमति देनी है, पहल लोक अभियोजक की है और अदालत को केवल यही करना है अपनी सहमति देना और किसी भी मामले को न्यायिक रूप से निर्धारित नहीं करना। सहमति देने के लिए न्यायिक विवेक के प्रयोग में निहित न्यायिक कार्य का आम तौर पर मतलब यह होगा कि अदालत को खुद को संतुष्ट करना होगा कि लोक अभियोजक के कार्यकारी कार्य का अनुचित तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है या यह न्याय के सामान्य पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं है। नाजायज़ कारणों या उद्देश्यों के लिए।

71. न्यायालय का कार्य सहमति देना है। यह धारा अदालत को सहमति देने से पहले कारण दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं करती है। हालाँकि, मुझे यह नहीं मानना चाहिए कि अदालत की सहमति निश्चित रूप से एक मामला है। जब लोक अभियोजक अपने समक्ष सभी सामग्रियों पर विचार करने के बाद वापसी के लिए आवेदन करता है, अदालत ऐसी सामग्रियों पर विचार करके अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करती है और इस तरह के विचार पर या तो सहमति देती है या सहमति देने से इनकार कर देती है। इस धारा का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि अदालत को सहमति देते समय एक

विस्तृत तर्कसंगत आदेश देना होगा। यदि पढ़ने पर सहमति देने वाले आदेश से उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसी सहमति उपलब्ध सामग्रियों के समग्र विचार पर दी गई थी, सहमति देने वाले आदेश को आवश्यक रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए।"

12. उक्त मामले में, बड़ी पीठ ने बंसी लाल बनाम चंदन लाल२, बलवंत सिंह बनाम बिहार राज्य३, सुभाष चंदर बनाम राज्य४, राजेंद्र कुमार जैन बनाम राज्य५, और बिहार राज्य बनाम राम में बताए गए सिद्धांतों का उल्लेख किया। नरेश पांडे६ और अंततः इस प्रकार कायम रहे:-

"उपरोक्त सभी निर्णयों में राम नरेश पांडे के मामले के तर्क का पालन किया गया है और उस निर्णय में तय किए गए सिद्धांत पर संदेह नहीं किया गया है। इन निर्णयों के आलोक में ही मामले पर विचार किया जाना है। मुझे वापसी के लिए आवेदन मिला है लोक अभियोजक को उसके समक्ष रखी गई सामग्रियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अच्छे विश्वास में बनाया गया है और मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सहमति का आदेश भी ऊपर बताए गए विभिन्न विवरणों पर उचित विचार करने के बाद दिया गया है। इस योजना को ध्यान में रखते हुए यह इस न्यायालय के लिए अनुचित होगा धारा 321 में मामले के तथ्यों और सबूतों की विस्तृत जांच शुरू करना या उसके लिए दोबारा सुनवाई का निर्देश देना धारा के उद्देश्य और इरादे को नष्ट करने वाला होगा।"

13. आर. एम. तिवारी, एडवोकेट बनाम राज्य ७ (एनसीटी दिल्ली) और अन्य मामले में इस न्यायालय ने अभियोजन से वापसी की न्यायसंगतता से निपटने के

दौरान संहिता की धारा 321 और उस सिद्धांत का उल्लेख किया जो श्योनंदनपासवान (सुप्रा) में कहा गया है और राय दी कि:-.

> "7. इसलिए, यह स्पष्ट है कि नामित न्यायालय का यह विचार सही था कि सरकारी अभियोजक द्वारा उस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर अदालत द्वारा अभियोजन से वापसी की यंत्रवत् अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि सरकारी वकील को भी समीक्षा समिति द्वारा की गई ऐसी सिफारिश पर सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अपने वैधानिक कार्य के निर्वहन में यांत्रिक रूप से कार्य नहीं करना है; और यह सार्वजनिक अभियोजक का कर्तव्य है कि वह खुद को संतुष्ट करे कि यह उपयुक्त है इससे पहले कि वह उस उद्देश्य के लिए अदालत की सहमति मांगे, मुकदमा अभियोजन से वापस ले लिया जाए।
>
> 8. ऐसा प्रतीत होता है कि इन मामलों में, सरकारी वकील ने सीआरपीसी की धारा 321 की आवश्यकताओं को पूरी तरह से नहीं समझा और केवल समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर अभियोजन से वापसी के लिए आवेदन किया। सरकारी वकील के लिए यह आवश्यक था कि वह प्रत्येक मामले में स्वयं को संतुष्ट करे कि मामला इस न्यायालय के निर्णयों में दर्शाए गए निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार अभियोजन से वापसी के लिए उपयुक्त है और फिर नामित न्यायालय को एक ऐसे आधार के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट करना जो वापसी की अनुमति देता है। सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन से।"

14. अब्दुल करीम आदि आदि बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य आदि८ में तीन न्यायाधीशों की पीठ। श्योनंदन पासवान मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया गया और भरूचा (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) ने खुद और न्यायाधिपति डी.पी. महापात्रा के लिए बोलते हुए इस प्रकार कहा: -

> "19. इसलिए, कानून यह है कि भले ही सरकार ने एक लोक अभियोजक को अभियोजन से हटने का आदेश दिया हो, निर्देश दिया हो या कहा हो, यह लोक अभियोजक का काम है कि वह सभी प्रासंगिक सामग्री पर अपना दिमाग लगाए और, अच्छे विश्वास के साथ, इस पर संतुष्ट होना होगा कि अभियोजन से उनके हटने से सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी। बदले में, अदालत को उन सभी सामग्रियों पर विचार करने के बाद संतुष्ट होना होगा कि लोक अभियोजक ने स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाया है, कि लोक अभियोजक, कार्य कर रहा है अच्छे विश्वास में, उसकी राय है कि अभियोजन से उसकी वापसी सार्वजनिक हित में है, और इस तरह की वापसी से कानून की प्रक्रिया बाधित या बाधित नहीं होगी या स्पष्ट अन्याय नहीं होगा।
>
> 20. धारा 321 के तहत आवेदन में यह अवश्य लिखा होना चाहिए कि लोक अभियोजक, सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद, सद्भावना से संतुष्ट है, कि अभियोजन से उसकी वापसी सार्वजनिक हित में है और यह प्रक्रिया को बाधित या विफल नहीं करेगी। कानून का या अन्याय का कारण। लोक अभियोजक ने जिस सामग्री पर विचार किया है, उसे आवेदन में या आवेदन के साथ संलग्न हलफनामे में या किसी दिए गए मामले में, एक सीलबंद लिफाफे में उसकी अनुमति के

साथ, अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए, संक्षेप में लेकिन संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अदालत को सूचित सहमति देनी होगी. उसे संतुष्ट होना चाहिए कि यह सामग्री उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि अभियोजन से लोक अभियोजक की वापसी सार्वजनिक हित में होगी; लेकिन सामग्री को तौलना अदालत का काम नहीं है। अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि लोक अभियोजक ने सामग्री पर और अच्छे विश्वास से विचार किया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन से उनकी वापसी सार्वजनिक हित में होगी। अदालत को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या सहमति देने से कानून की प्रक्रिया बाधित हो सकती है या इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट अन्याय हो सकता है। यदि इस तरह के विचार पर अदालत सहमति देती है, तो उसे ऐसा करना ही चाहिए। आवेदन पर ऐसा आदेश दें जिससे उच्च न्यायालय को यह संकेत मिले कि उसने सहमति देने से पहले वह सब कुछ कर लिया है जो कानून के अनुसार करना आवश्यक है।" (जोर दिया गया)

15. न्यायाधिपति वाई.के. सभरवाल (जैसा कि उनका आधिपत्य तब था) ने संहिता की धारा 321 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक मूलभूत मापदंडों पर आगे विस्तार से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि:-

"42. सीआरपीसी की धारा 321 के तहत एक आवेदन दायर करने की संतुष्टि लोक अभियोजक की होनी चाहिए, जो मामले की प्रकृति के अनुसार राज्य द्वारा प्रदान की गई सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति धारा 321 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय ने श्योनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य

मामले में इस न्यायालय के फैसले को रेखांकित किया है। यह निर्णय मानता है कि अदालत द्वारा सहमति प्रदान करना कोई स्वाभाविक बात नहीं है और जब इस तरह का आवेदन दायर किया जाता है लोक अभियोजक उसके सामने मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, अदालत ऐसी सामग्री पर विचार करके अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करती है और इस तरह के विचार पर या तो सहमति देती है या सहमति से इनकार करती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अदालत को यह देखना होगा। आवेदन अच्छे तरीके से किया गया है विश्वास, सार्वजनिक नीति और न्याय के हित में और कानून की प्रक्रिया को विफल या बाधित करने में नहीं या ऐसी अनुचितताओं या अवैधताओं से ग्रस्त है जिससे सहमति दिए जाने पर स्पष्ट अन्याय हो सकता है।

43. सच है, धारा 321 के तहत न्यायालय की शक्ति पर्यवेक्षी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस शक्ति का प्रयोग करते समय, केवल पूछने पर सहमति दी जानी चाहिए। अदालत को यह जांचना होगा कि लोक अभियोजक और/या सरकार द्वारा अपने कार्यकारी कार्य के अभ्यास में सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया गया है।"

[रेखांकित करना हमारा है]

16. राहुल अग्रवाल बनाम राकेश जैन और अन्य में न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि संहिता की धारा 321 के तहत वापसी के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय कानूनी विचार क्या होना चाहिए। न्यायालय ने राम नरेश पांडे (सुप्रा), उड़ीसा राज्य बनाम चंद्रिका महापात्रा१०, बलवंत सिंह बनाम बिहार राज्य (सुप्रा) और अब्दुल करीम (सुप्रा) में प्राधिकरण के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें संविधान

पीठ के पहले के फैसले थे। श्योनंदन में पासवान की सराहना की गई और अब्दुल करीम (सुप्रा) के कुछ अंशों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद फैसला सुनाया गया कि: -

> "10. इन निर्णयों के साथ-साथ इसी प्रश्न पर अन्य निर्णयों से, कानून बहुत स्पष्ट है कि अभियोजन को वापस लेने की अनुमति केवल न्याय के हित में दी जा सकती है। भले ही सरकार लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने का निर्देश दे और एक इस आशय का आवेदन दायर किया गया है, अदालत को सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या अभियोजन वापस लेने से न्याय की दिशा में प्रगति होगी। यदि मामले का अंत बरी होने की संभावना है और मामले को जारी रखने से केवल गंभीर उत्पीड़न हो रहा है अभियुक्त को, अदालत अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे सकती है। यदि अभियोजन वापस लेने से विवाद खत्म होने और पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित होने की संभावना है और यह न्याय के सर्वोत्तम हित में होगा, तो अदालत अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत विवेक का प्रयोग अदालत द्वारा सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो कि पीड़ित पक्षों या राज्य के अनुरोध पर किया जा रहा है। उनकी शिकायत का निवारण करना। प्रत्येक अपराध समाज के प्रति अपराध है और यदि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है। समाज की मांग है कि उसे सजा मिलनी चाहिए. अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को दंडित करना समाज में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता है। इसलिए, अभियोजन वापस लेने की अनुमति

केवल तभी दी जाएगी जब इसके लिए उचित कारण बताए जाएंगे।"

(महत्व जोड़ें]

17. प्राप्त तथ्य स्थिति का परीक्षण उपरोक्त कानून के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसा कि प्रदर्शित है, राज्य सरकार ने जी.ओ. संख्या 268 दिनांक 23 मई, 2009 के माध्यम से कुछ पहलुओं की गणना की है जिन्हें यहां पहले पुनः प्रस्तुत किया गया है। पुनरुत्पादन भाग में थोड़ा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश में, तीसरा संदर्भ श्री बी. मुरलीधर, पुलिस उप-निरीक्षक, कामारेड्डी टाउन पी.एस. के प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है। दिनांक 5.8.2007 और चौथा संदर्भ महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के दिनांक 12.10.2007 के संचार को संदर्भित करता है। इसके बाद राज्य सरकार ने अपनी राय दी कि केस वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी. विद्वान लोक अभियोजक ने अभियोजन वापस लेने के अपने आवेदन में सरकारी आदेश का हवाला दिया है और अदालत से अनुमति मांगी है। सरकारी वकील ने जो कहा है वह यह है कि उन्होंने सरकारी आदेश, रिकॉर्ड पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों का अध्ययन किया है और स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाया है और संतुष्ट हैं कि यह वापसी के लिए उपयुक्त मामला है।

18. केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या सरकारी वकील ने वास्तव में रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर अपना दिमाग लगाया है और खुद को संतुष्ट किया है कि अभियोजन से हटने से सार्वजनिक हित का उद्देश्य पूरा होगा या नहीं। जैसा कि कहा गया है, यह उसका दायित्व है सरकारी वकील को यह बताना होगा कि उसने किस सामग्री पर विचार किया है। इसे संक्षेप में बताना होगा। जैसा कि अब्दुल करीम के मामले में माना गया है, न्यायालय को एक सूचित सहमति देना आवश्यक है। न्यायालय के लिए स्वयं को संतुष्ट करना अनिवार्य है कि सामग्री के आधार पर यह उचित रूप से माना जा सकता है कि अभियोजन वापस लेने से सार्वजनिक हित में

मदद मिलेगी। सामग्री को तौलना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तथापि; न्यायालय के लिए यह देखना आवश्यक है कि क्या सहमति देने से कानून का मार्ग बाधित होगा या बाधित होगा या स्पष्ट अन्याय होगा। संहिता की धारा 321 के तहत सहमति देते समय एक न्यायालय को अपने न्यायिक विवेक और न्यायिक विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि कानून में तय न्यायिक विवेक का प्रयोग यांत्रिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट सिर्फ पूछने पर ऐसी सहमति नहीं दे सकता. न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करे आवेदन अच्छे विश्वास में दायर किया गया था और यह सार्वजनिक हित और न्याय के हित में है। एक अन्य पहलू यह है कि न्यायालय यह देखने के लिए बाध्य है कि क्या इस तरह की वापसी न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगी। इसमें सावधानीपूर्वक और चिंतित विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ अपराध राज्य और समाज के खिलाफ हैं क्योंकि सामूहिक रूप से न्याय की मांग की जाती है। जो समाज में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखता है। लोक अभियोजक राज्य सरकार की ओर से डाकघर की तरह कार्य नहीं कर सकता। उनसे सद्भावना से कार्य करने, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का अध्ययन करने और एक स्वतंत्र राय बनाने की अपेक्षा की जाती है कि मामले को वापस लेने से वास्तव में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित में मदद मिलेगी। इस संबंध में सरकारी वकील पर सरकार का आदेश बाध्यकारी नहीं है। वह संहिता के तहत अपने कानूनी दायित्वों से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। उनसे न्यायालय के प्रति अपने कर्तव्य के साथ-साथ सामूहिकता के प्रति अपने कर्तव्य को लगातार याद रखने की आवश्यकता है। मौजूदा मामले में, जैसा कि सरकारी वकील द्वारा दायर आवेदन से पता चलता है कि उसने यांत्रिक रूप से शर्तों-मिसाल के बारे में कहा था। यह नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में सामग्रियों का अध्ययन किया है और अपना स्वतंत्र दिमाग केवल इसलिए लगाया है क्योंकि उसने ऐसा कहा है। आवेदन में यह बताते हुए सामग्री का अवलोकन करना चाहिए कि उसने किन सामग्रियों का

अध्ययन किया है, संक्षेप में हो सकता है, और क्या अभियोजन को वापस लेने से सार्वजनिक हित में मदद मिलेगी और उसने अपनी स्वतंत्र राय कैसे बनाई है। जैसा कि हम समझते हैं, विद्वान लोक अभियोजक पूरी तरह से सरकार के आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है और वास्तव में मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। विद्वान विचारण न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी देखा है कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामला है। उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि राज्य सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पाया है कि अभियोजन वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है

19. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले की अपनी गंभीरता होती है। निरंजन हेमचंद्र सशित्तल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य११ में विलंबित मुकदमे के आधार पर अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता पर आय से अधिक संपत्ति के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। उक्त अधिनियम का एक उद्देश्य है। संसद का उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना और आपराधिक दोष साबित होने पर निवारक दंड प्रदान करना है। इरादा विधायिका की अत्यधिक सामाजिक प्रासंगिकता है। वर्तमान परिदृश्य में, भ्रष्टाचार को अर्थव्यवस्था के मज्जा को नष्ट करने की क्षमता वाला माना गया है। ऐसे मामले हैं जहां राशि छोटी है और कुछ मामलों में, यह बहुत अधिक है। ऐसे मामले में, हमारी सुविचारित राय में, अपराध की गंभीरता को रिश्वत की मात्रा के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए। लाभ के बदले में लाभ पहुंचाने के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का रवैया सामूहिक और एक

के खिलाफ अपराध है यह लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के लिए अभिशाप है, क्योंकि यह व्यवस्था में लोगों के विश्वास को खत्म कर देता है। यह कानून के शासन में एक असाध्य विसंगति पैदा करता है। ध्यान दें, सुशासन की प्रणाली संस्थानों में सामूहिक विश्वास पर आधारित होती है। यदि अन्य प्रासंगिक कारकों की जांच किए बिना केवल देरी के कारण भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही को रद्द करने की अनुमति देकर भ्रष्टाचार जारी रखा जाता है, तो एक समय आ सकता है जब बेईमान लोग बढ़ावा देंगे और अराजकतावाद का मार्ग प्रशस्त करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।"

20. हाल ही में, ओर. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य१२, संविधान पीठ ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 ए, जिसे 2003 के अधिनियम 45 द्वारा डाला गया था, को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा है कि: -

"हमें ऐसा लगता है कि सरकारी सेवा में स्थिति के आधार पर धारा 6-ए में जो वर्गीकरण किया गया है, वह अनुच्छेद 14 के तहत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रथम दृष्टया सत्य खोजने के उद्देश्य को विफल करता है, जो कि पीसी अधिनियम, 1988 के तहत एक अपराध। क्या भ्रष्ट लोक सेवकों के बीच उनकी स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि उनकी स्थिति या स्थिति के बावजूद, भ्रष्ट लोक सेवक सार्वजनिक शक्ति के भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट लोक सेवक चाहे उच्च हों या उच्च निम्न, एक ही पंख के पक्षी हैं और जांच और पूछताछ की प्रक्रिया का समान रूप से सामना किया जाना चाहिए। सेवा में स्थिति या स्थिति के आधार

पर उन लोक सेवकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है जिनके खिलाफ पीसी अधिनियम 1988 के तहत अपराध के आरोप हैं।"

और उसके बाद, बड़ी बेंच ने आगे फैसला सुनाया:

"भ्रष्टाचार राष्ट्र का दुश्मन है और भ्रष्ट लोक सेवकों पर नज़र रखना और ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना पीसी अधिनियम, 1988 का एक आवश्यक आदेश है। धारा 6-ए में जो वर्गीकरण किया गया है उसे उचित ठहराना मुश्किल है क्योंकि कानून का लक्ष्य पीसी अधिनियम, 1988 में भ्रष्टाचार के मामलों को बहुत सख्ती से निपटाने का प्रावधान है और सभी लोक सेवकों को ऐसे विधायी उपाय के माध्यम से चेतावनी दी जाती है कि भ्रष्ट लोक सेवकों को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।"

और फिर, बड़ी बेंच ने कहा:

"70. सार्वजनिक सत्ता का कार्यालय व्यक्तिगत लाभ की कार्यशाला नहीं हो सकता। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का बहुत महत्व है। दो लोक सेवक जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या रिश्वत लेने या पीसी अधिनियम 1988 के तहत आपराधिक कदाचार के आरोप हैं, वे कैसे ऐसा कर सकते हैं? उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि एक कनिष्ठ अधिकारी होता है और दूसरा वरिष्ठ निर्णय लेने वाला होता है।

71. भ्रष्टाचार राष्ट्र का दुश्मन है और भ्रष्ट लोक सेवक पर नज़र रखना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, और ऐसे व्यक्ति को दंडित करना पीसी अधिनियम, 1988 के तहत एक आवश्यक आदेश है। लोक सेवक

की स्थिति या स्थिति ऐसे लोक सेवक को योग्य नहीं बनाती है। समान व्यवहार से छूट. निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में विभाजित नहीं करती है क्योंकि वे सामान्य अपराध करने वाले होते हैं और उन्हें पूछताछ और जांच की एक ही प्रक्रिया द्वारा ट्रैक किया जाना चाहिए!"

21. हमने इन प्राधिकारियों को केवल यह दिखाने के लिए संदर्भित किया है कि मामले में, सार्वजनिक अभियोजक द्वारा दायर आवेदन की प्रकृति के अलावा अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हम सुविचारित राय पर हैं विद्वान विचारण न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार में गलती नहीं पाई जा सकती। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि यह दिखाने का कोई आधार नहीं है कि इस तरह की वापसी से न्याय का उद्देश्य आगे बढ़ेगा और सार्वजनिक हित में मदद मिलेगी। इसके अलावा, विद्वान लोक अभियोजक की ओर से स्वतंत्र रूप से दिमाग का कोई प्रयोग नहीं किया गया, संभवतः यह सोचकर कि न्यायालय केवल पूछने पर आदेश पारित कर देगा। नाम दशरथ के मामले (सुप्रा) में व्यक्त विचार मौजूदा मामले पर लागू नहीं होता है जैसा कि दो न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी है कि श्योनंदन पासवान के मामले में निर्धारित कानून की विद्वान विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से सराहना नहीं की गई है। हमने उक्त प्राधिकारी का उल्लेख किया है और बाद के निर्णय जो कि श्योनंदन पासवान के मामले पर आधारित हैं, ने लोक अभियोजक के कर्तव्य और न्यायालय की भूमिका से संबंधित सिद्धांतों को निर्धारित किया है और हम विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को पाते हैं। और उच्च न्यायालय बिल्कुल अभेद्य है और इसलिए, दशरथ नाम (सुप्रा) में निर्णय तथ्यों पर अलग है।

22. परिणामस्वरूप, बिना किसी आधार के आपराधिक अपील खारिज कर दी जाती है।

राजेंद्र प्रसाद

अपील खारिज की आती हैं।

---

१ ए आई आर 1987 एस सी 877

२ 2. एआईआर 1976 एससी 370

३. (1978) 1 एससीआर 604

४. (1980) 2 एससीआर 44

५ एआईआर 1980 एससी 1510

६. एआईआर 1957 एससी 389

७. (1996) 2 एसईसी 610

८ ए आई आर 2001 एस सी 116

९ (2005) 2 एस सी ई 377

१० (1976) 4 एस सी सी 250

११ (2013) 4 एसईसी 642।

१२ रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 38/1997 आदि दिनांक 06 मई 2014 को सुनाया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।